16.20 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377—*Contd.*

(v) Need to send a team of doctors for proper treatment and care of the injured in Assam.

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj): I am pained to mention that there has been large scale massacre in Assam, without any rhyme or reason. For the present, I do not want to go into the merits of the massacre, but it is a hard fact tht there has been large-scale massacre. What is pinching me most is that the injured persons, who have been admitted to the hospitals, are not being given medical facilities and treatment only on the ground that they belong to a particular community and also on the ground of language and religion. It is most heartrending that the patients are being looked after and treated on the basis of language and religion. Furthermore, I may mention with a full sense of responsibility that the injured persons are administered such medicines which are hazardous to the life of the patents and which will end the life of the patients.

So, I feel strongly that a host of Central team of doctors should be sent immediately for proper care of the injured persons in Assam. I also urge that the Assam Police be disarmed and the BSF and Central Reserve Police and sent in large number so that peace may prevail and all people may live in security and safety.

16.21 hrs.

MEMBER SWORN

SHRI BAJUBON R. KHARLUKHI (Shillong-Meghalaya).

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up Private Members' Business-

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Fifty-fourth Report

SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA (Arrah): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Reolutions presented to the House on the 2nd March, 1983."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 2nd March, 1983."

The motion was adopted.

16.23 hrs.

RESOLUTION RE: STEPS FOR SPEEDY IMPLEMENTATION OF SOCIO-ECONOMIC PROGRAMME—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now resume discussion on the following Resolution moved by Shri K. Lakkappa on 13th August, 1982 on Speedy Implementation of Socio-Economic Programme:

"Keeping in view the vital need for speedy implementation of the socio-economic programme of the Government, this House recommends the setting up of a monitoring body under the Govrenment to constantly watch the progress of the different developmental activities at all levels, locate the factors hampering the progress and suggest immediate and remedial measures to expedite their implementation.."

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री लकप्पा ने जो संकल्प यहां पेश

किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि सरकार जो आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित करती है, उन्हें अमल में लाया जाता है या नहीं, इसी बात को देखने के लिए कोई मानिटरिंग बाडी, समिति, निकाय या संगठन होना चाहिये। यह इन्होंने बहुत ही मुनासिब बात कही है।

हम सभी अपने अनुभव से जानते हैं कि सरकार बहुत तरह की योजनाएं चालू करती है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन उसका रिटर्न या फायदा जितना होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है। बहुत सारे रुपयों का दुरुपयोग हो जाता है और उसको पकड़ में लाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं रहती है। सरकारी अधिकारी जो चाहते हैं, करते हैं, मंत्री लोग भी उसको ठीक ढंग से नहीं पकड़ पाते। अगर वह पकड़ना भी चाहें तो तरह-तरह की कठिनाइयां उन योजनाओं की क्रियान्विति में होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि योजना पूरी नहीं होती है और बहुत सारा पैसा वापिस चला जाता है।

अभी कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि एन आर ई पी योजना का 47 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने सेन्टर को वापिस कर दिया और वहां बिना काम के लोग इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इसी तरह की बात दूसरे कामों में भी होती है। बीस सूत्री कार्यक्रम में अभी दस हजार करोड़ रुपया फिर नये बजट के जरिए उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवंटित करने की बात कही गई है। मैं अपने जिले में, बीस-सूत्री कार्यक्रम चलाने के लिए जो कमेटी है, उसका सदस्य हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उस बैठक में जाकर हिस्सा लूं लेकिन कभी-कभी नहीं भी जा पाता हूं। हर जिले में उस कमेटी का अध्यक्ष को कैबिनेट या दूसरा मिनिस्टर बनाया गया है लेकिन अनुभव यह बताता है कि जब भी मीटिंग होती है उसमें एक ही बात दोहराई जाती है कि लैण्ड रिफार्म हुआ और यह नहीं हुआ। जिलों में बहुत सारे ट्यूबवैल्स गाड़े गए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस होती हैं। लेकिन मैं आपको पटना जिले की बात बताऊं कि तीन-चार मीटिंग्स से यही बताया जाता है कि 400 ट्यूबवैल खराब हैं। कुल 600 ट्यूबवैल गाड़े गए हैं जिनमें 200 काम करते हैं और 400 बेकार पड़े हैं। हर मीटिंग में उनको ठीक करने की मांग की जाती है। किसी में तो बिजली का कनेक्शन नहीं है, किसी में चैनल नहीं है, कहने का मतलब यह है कि 400 काम में नहीं आते हैं। इस साल बिहार में जबर्दस्त सुखाड़ पड़ा जिसके बारे में वक्तन-फवक्तन इस सदन में भी चर्चा की जा चुकी है और आगे भी हो सकती है। एक ओर तो सुखाड़ है और दूसरी ओर 400 ट्यूबवैल काम नहीं करते हैं। उनको

16.28 hrs.

[Shri Chintamani Panigrahi in the chair]

देख-भाल के लिए अधिकारी जरूर हैं लेकिन उनको भी चिन्ता नहीं रहती। वजह जो भी हो, वे देखते नहीं हैं। इस तरह से आप जो जनता का इतना पैसा विकास कार्यों के लिए देते हैं उससे वह कार्य हो नहीं पाता है। अतः इस तरह की कोई कमेटी बनायें जो इन बातों को देखे। यह कमेटी आप सारे देश के स्तर पर बना सकते हैं--मानिटरिंग कमेटी--राज्यों के स्तर पर बना सकते हैं, जिलों के स्तर पर बना सकते हैं, जहां भी आप मुनासिब समझें बनाकर देखें कि सच-मुच में काम होता है या नहीं। अफसरान के अलावा भी आप कोई दूसरा अंकुश रखिए। मैं समझता हूं लकप्पा साहब के दिमाग में यह नहीं होगा कि मानिटरिंग कमेटी में केवल अधिकारियों और मंत्रियों को ही रखा जाए। मैं समझता हूं सभी दलों के प्रतिनिधियों को उसमें रखा जाना चाहिए। अभी बीस-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित कमेटी में तमाम पार्टीज के लोगों को नहीं रखा गया है। मैंने एक मीटिंग में यह सवाल उठाया था कि सारे कांग्रेसी ही क्यों हैं? मुझे तो एम पी की हैसियत से रखा गया है लेकिन वहां कांग्रेस (एस) के एम एल ए हैं, रामलखन सिंह यादव को नहीं रखा गया है। लोकदल के किसी मेम्बर को भी नहीं रखा गया है, उसके भी एम एल ए मौजूद हैं। ज्यादातर कांग्रेसी लोगों को ही एम पी और एम एल ए के नाम पर भर दिया गया है, एकाध पार्टी को ही जगह दी है। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिनको ईमानदारी के साथ में लाने की कोशिश की जाती, तो कुछ काम किया

[श्री रामावतार शास्त्री]

जा सकता है । व्यान्वित किया जा सकता है । विकास कार्यों में प्रगति लाई जा सकती है और गरीबों की मदद की जा सकती है । उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें हम जाना नहीं चाहते हैं । भूमिसुधार के सिलसिले में, बिजली के सिलसिले में, झुग्गी-झोंपड़ी के सिलसिले में, लेकिन अभी आप क्या करते हैं जिसको चाहते हैं, उसको उजाड़ देते हैं । पटना के बारे में मैं आपको बता सकता हूं । वहां पर बड़े पैमाने पर उजाड़ा जा रहा है । अगर विरोध करते हैं, तो हरिजनों की हत्यायें हो जाती हैं । अभी एक सीताराम पासवान की हत्या कर दी गई। मारते-मारते पुलिस लार्कअप में ले गई । इतना मारा कि वह मर गया । उसके पिता को कह दिया कि यह डकैत था । मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिए वह डकैत था, तो क्या उसको जान से मार दिया जाएगा । यह कहां का कायदा है । झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को नए मकान देने की बात कही गई है । बुनकरों की समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ बातें कही गई हैं । बातें बहुत अच्छी अच्छी कही गई हैं लेकिन उनका कार्यान्वियन नहीं होता है । बैठकों में हम जाते हैं, बहुत सारे तो टी.ए./डी.ए. लेकर चलते जाते हैं और काम जहां-का-तहां रह जाता है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम का काम ठीक से चले तो उसमें सभी दलों के लोगों को शामिल कीजिए । एक दफा बिहार के चीफ मिनिस्टर यहां आए थे, तो उन्होंने मीटिंग में पार्लियामेंट के मेम्बर के सामने कह दिया कि लोकदल ने इन्कार कर दिया, उस कमेटी में रहने से । उसी वक्त लोकदल के मेम्बर ने उठ कर कहा कि यह गलत बात है । मैं उस कमेटी में चलने को तैयार हूं । फिर भी सबों को नहीं लेते हैं । यदि 20 सूत्री कार्यक्रम में भी पार्टी बाजी होगी तो काम ठीक नहीं चलेगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सोवियों-इक्वानोमिक काम आगे बढ़ाने के लिए जो आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । कन्ट्रैक्टर बीच में न खा जायें, नेता लोग न खा जायें, मिनिस्टर लोग न खा जायें, इसका आपको ख्याल रखना होगा । पैसा ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं, काम पूरा होता है या नहीं, जिस तरह से एस्टीमेट कमेटी जांच करती है, उसकी जांच होनी चाहिए। सोशियो-इकानोमिक कार्यक्रम के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की मोनिटरिंग कमेटी का गठन होना चाहिए और सब तरह के लोगों को उसमें रखना चाहिए । अखिल भारतीय स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए । जो इस चीज की जांच करे कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो लकड़ावाला जी ने जो संकल्प पेश किया है, उसका कुछ नहीं हो सकता है । हम लोग विभिन्न मुद्दों के बारे में आपको फीगर्स दे सकते हैं । आपको स्वयं आपके सूबे का अनुभव होगा । मैं तो बिहार से आता हूं, बिहार के बारे में आपको बता सकता हूं । 25 परसेंट रुपया भी विकास कार्यों पर खर्च नहीं होता है । हम चाहते हैं कि पूरी रकम खर्च हो अन्यथा 75 परसेंट रुपया तो खर्च होना ही चाहिए । गोल माल कुछ नहीं होना चाहिए । लेकिन फिर भी आपको ज्यादा हिस्सा तो देना चाहिए । मोनिटरिंग कमेटी बनाकर आपको पावर देनी चाहिए । आपके श्रम विभाग की कमेटी है, योजना विभाग की कमेटी है, रेलवे कन्सलटेटिव कमेटी है, लेकिन उसमें भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं, पर उन निर्णयों का कितना पालन होता है । नहीं होता है । इसी तरह से बहुत सारी योजनायें हमारे देश में चल रही हैं । हमारा देश विकासमान देश है, उसमें बहुत सारी समस्यायें आयेंगी, धीरे-धीरे आप उन को हल करते जायेंगे। समस्यायें फिर आयेंगी, फिर उनको हल करेंगे । इसके लिए जरूरी है कि वाच-डाग का काम करने के लिए आप कमेटी बनाइए, जिस पर आर्थिक व्यवस्था पर भी उसका अधिकार हो और इसके साथ योजना को भी कार्यान्वित करने का अधिकार हो ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को अगर आप अमल में लाना चाहते हैं तो सब तरह के लोगों को लाइए । उसमें आप 10 हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन वह पैसा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है । जो सचमुच डाउन-टाडन हैं,

बिल्कुल निम्न-स्तर के गरीब किसान हैं, जो खेती में लगातार काम करते हैं उन को साढ़े आठ रुपये मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं । वह कमेटी इस बात को भी देखे कि क्यों नहीं दे रहे हैं ।

मैं वह भी चाहता हूं कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की कमेटी बनाई जाय, तभी हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, लकप्पा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । उन्होंने इस सदन के माध्यम से इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का जो अवसर दिया है, इस के लिए मैं उन का आभारी हूं । मैं उन से इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने जो चार्ज लगाया है--आज का जो ब्यूरोक्रेटिक सेट-अप है, उस में जो नौकरशाही दृष्टि है, वह हमारी सोशियो-इकानामिक दृष्टि से बिलकुल विपरीत है। हमारी दृष्टि कुछ और है और जो हमारे नौकरशाह हैं जिन के माध्यम से हम काम करवाते हैं, उन की दृष्टि कुछ और है ।

लेकिन मैं इस में उन से यह भी आग्रह करना चाहूंगा--वे जरा इस पर भी गौर करें कि किसी भी परिवर्तन के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है---पहली तो यह कि परिवर्तन करने वाले की स्वयं की नीयत साफ है या नहीं । दूसरे---यदि उस की नीयत साफ हो, तो उस के अनुपात से नीति बन रही है या नहीं । अब नीति बनती है तो तीसरी स्टेज यह आती है कि नीति का कार्यान्वयन कैसे हो रहा है । ये तीन फेसेज हैं ।

सभापति महोदय, आजादी के 35 साल बाद हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस के पहले भी यह चर्चा यहां पर हमेशा होती रही है, लेकिन यदि हम एक-एक कर के देखें तो आप पहले आर्थिक और सामाजिक मुद्दे को लीजिये---हम उस के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये मानिटिरिंग-सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस में सब से पहला वाइटल ईशु है --- जमीन का मामला । मैंने इस सदन में एक प्रश्न पूछा था कि हमारे पास कितनी जमीन कृषि योग्य है । जवाब दिया गया---185 मिलियन हैक्टेअर है । उस के बाद मैंने पूछा कि इस जमीन में से सिंचाई कितने में हो सकती है यानी कितनी इरिगेटेड लैंड है । मुझे जवाब मिला---37 मिलियनन हैक्टेअर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है । आप देखिये---35 साल की आजादी के बाद 37 मिलियन हैक्टेअर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है, बाकी में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ।

प्रतिदिन भूमि सुधार की बात कही जाती है । हम इस के लिये नौकरशाह लोगों को पकड़ सकते हैं, लेकिन दिशा-निदेश तो आप करते हैं । सवारी अगर मजबूत होती है तो घोड़ा ठीक चाल से चलता है, लेकिन सवारी कमजोर होती है तो घोड़ा पटक कर चला जाता है । मैं ऐसा नहीं मानता कि इन्दिरा जी सवारी करने में कोई कमजोर सवार है । जो वह चाहें, वह न हो, ऐसी बात मेरे दिमाग में नहीं है । मैंने उस के बाद फिर प्रश्न पूछा---कि आप के पास सरप्लस लैंड कितनी है ? जवाब मिला---53 लाख एकड़ जमीन सरप्लस है । मैंने फिर पूछा---उस में से सरकार ने अपने कब्जे में कितनी की है तो जवाब मिला---40 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ली है । मैंने पूछा---बटवारा कितनी जमीन का किया गया है, जवाब मिला---17 लाख एकड़ जमीन का बटवारा हुआ है । आप देखिये---53 लाख एकड़ जमीन में से 17 लाख एकड़ जमीन का बटवारा हुआ है। आप देखिये-53 लाख एकड़ जमीन में से केवल 17 लाख एकड़ जमीन का बटवारा सरकार जिम्मेदार नहीं है ? क्या सरकार इस बारे में अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है ? यह तो मैं जानता हूं कि सरकार यह कह सकती है कि जमीन वाले लोग कोर्ट में चले जाते हैं और वहां वे इसको एकवा देते हैं । लेकिन आपके पास पार्लियामेंट में दो तिहाई बहुमत है, आप ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे समस्या का समाधान सदा के लिए हो जाए । आप अपने बहुमत के बल पर इसको पार्लियामेंट में निबटा सकते हैं । इसलिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी अगर नीयत साफ हो तो सब काम हो सकता है ।

[श्री रामविलास पासवान]

हमारे देश में पौने छह लाख गांव हैं । आजादी के 35 साल के बाद भी हमारे देश के 50 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है । हम दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो फव्वारे चले होते हैं । कल हम ताजमहल होटल से आ रहे थे जहां पर कि हमें विदेश मंत्री ने बुलाया था । वहां से जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि दोनों तरफ 25-25 गज का कपड़ा टंगा हुआ है । कहा जाता है कि आठ लाख गज कपड़ा इसमें लगा है । इस आठ लाख गज कपड़े में से कम से कम दो लाख गरीब लोगों की गंजी बन सकती थी। हमारे गांवों में लोग गर्मी में, सर्दी में भूख से मर रहे हैं । सर्दी में ठिठुर कर और गर्मी में लू से मर रहे हैं । उनके लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं है । दिल्ली में फव्वारा चलाने के लिए सरकार के पास पैसा है ।

पार्लियामेंट के बगल में राजेन्द्र प्रसाद रोड़ पर पंत जी का स्टेच्यू है । वहां बारहों महीना फव्वारा चलता रहता है । हमने कहा कि भाई इनको ठंड लग जाएगी, इन्हें ठंड से क्यों मार रहे हो ? एक तरफ यह हालत है और दूसरी तरफ गांवों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता । आज भी आप गांवों में जाकर देखें कि जिस पोखर में गाय, भैंस आदि जानवर नहाते हैं, उसी का पानी गांव का आदमी पीता है । गांवों में औरतें और आदमी महीनों तक नहाते नहीं है । इसलिए नहीं नहाते हैं कि उनके पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है । महीने-दो महीने बाद औरतें और आदमी पोखर पर जा कर नहाते हैं और उसी कपड़े को धो, सूखा कर दुबारा पहन कर घर पर लौटते हैं । एक तरफ गरीबी का यह आलम है और दूसरी तरफ दिल्ली में यह शान शौकत है ।

मैं एशियाड खेलों का विरोधी नहीं हूं क्योंकि हम लोग बीसवीं शताब्दी में रह रहे हैं । मैंने उस दिन भी आप से कहा था कि अगर आपने राजस्थान को नहर पूरी करने के लिए चार सौ करोड़ रुपया दिया होता तो आज राजस्थान का सूखा इलाका हराभरा हो जाता और आपको चार सौ करोड़ रुपये के बदले में एक हजार करोड़ रुपया दिया होता । लेकिन हमारे सामने प्रायोरिटी ही नहीं है । हमने एशियाड को प्रायोरिटी दी । इसलिए दी कि उसमें सीधे-सीधे कमीशन बचता था । वह चाहे अफसरों को बचा हो, या किसी और को बचा हो । आप एशियाड दस साल के बाद भी करवा सकते थे । (व्यवधान) अगर हम दस साल के अन्दर, पांच साल के अन्दर राजस्थान में नहर का जाल बिछा देते तो हम को चार सौ करोड़ रुपये के बदले में चार हजार करोड़ रुपया मिल गया होता । लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है ।

आज 35 साल की आजादी के बाद भी 50 परसेंट लोग हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे हैं । 25 परसेंट लोग शिक्षित हैं और 75 परसेंट लोग अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, हमारे यहां सबसे ज्यादा सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा होती है लेकिन फिर भी हमारे यहां सब से ज्यादा कंगाली है, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है ? हो सकता है कि मशीनरी खराब हो लेकिन क्या इसके लिए भी सरकार की जवाबदेही नहीं है ?

मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पर पीछे बोल रहा था तो मैंने कहा था कि सरकार जो योजना बनाती है, उससे हम 16 साल पीछे चले जाते हैं । क्योंकि कोई भी योजना हमने दो करोड़ की बनायी, वह योजना के पूरे होने में डिले होती जाती है और उसकी कास्ट बढ़ती जाती है । इस तरह से वह 16 साल पीछे चली जाती है । प्रधान मंत्री जाएंगी तो पत्थर गाड़ देंगी, फिर कोई मंत्री जाएगा वह पत्थर गाड़ देगा। कम शिलान्यास कीजिए, लेकिन उन योजनाओं को पूरा कीजिए । ऐसा न हो कि यहां भी योजना शुरू कर दी, 6 महीने बाद वह बंद हो गई, दूसरी शुरू कर दी । योजनाओं को लागू करने का काम किया जाए, नहीं तो यह हमारा या आपका लास नहीं है यह पूरे देश का लास है । देश को सबसे पहले सामने रखना होगा । आज आप हैं कल हम हो सकते हैं फिर आप आ सकते हैं, लेकिन

देश सर्वोपरी है । हम रहें या न रहें, देश हमेशा आगे रहना चाहिए ।

कल विद्युत मंत्री जी जवाब दे रहे थे । सोशियो इकनामिक प्रोग्राम में क्या है । इसके लिए आपको विद्युत चाहिए, रोड चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ये सब चीजें देश को विकास के मार्ग में आगे बढ़ाती हैं । लेकिन कल विद्युत मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, हम तो करना चाहते हैं, विद्युत बोर्ड तैयार नहीं है, बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। यह सब आप किसको सुना रहे हैं ।

दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स को देखकर आश्चर्य होता है । उसमें जो फार्म भरे जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि मां-बाप क्या करते हैं, अंग्रेजी जानते हैं या नहीं जानते हैं ? अब ऐसे माहौल में कोई गांव का आदमी कैसे सोच सकता है कि उसका बच्चा भी पब्लिक स्कूल में पढ़ सकता है । उसका लड़का कैसे एस डी ओ या कलेक्टर बन सकता है । आप क्या करना चाहते हैं । आप कीचड़ में कुछ कमल खिलाना चाहते हैं । इसलिए पब्लिक स्कूल्स पर कुछ अंकुश लगाने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय : रेजोल्यूशन में पब्लिक स्कूल भी आते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : सोशियो इकनामिक प्रोग्राम में तो आता ही है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके केन्द्रीय विद्यालयों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है । इस तरह के विद्यालय जिला स्तर पर खोले जाएं । ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, नाम इनका पब्लिक स्कूल है, इनमें कुछ पर-सेंटेज फिक्स किया जाना चाहिए कि इतने गांवों के गरीब-गुरबा लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा । अगर यह व्यवस्था नहीं की गई तो शिक्षा में समानता नहीं आ सकती। इसलिए हमने एक नारा दिया है—

राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान,
ब्राह्मण या भंगी का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान ।

जहां से बच्चा आगे बढ़ता है, वहां पर तो कम से कम उससे समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर शिक्षा समान स्तर पर लागू नहीं की गई तो एक स्कूल चपरासी पैदा करेगा और एक स्कूल कलेक्टर पैदा करेगा। इस तरह से यह सोशियो इकनामिक प्रोग्राम में आता है ।

भ्रष्टाचार के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि पूरे विश्व में है, लेकिन इससे काम नहीं चल जाता है । क्योंकि संसार में भ्रष्टाचार है इसलिए भारत में भ्रष्टाचार का चलना कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इस देश में 50 लाख बंधुआ मजदूर हैं । आजादी के बाद भी 12 परसेंट लोग विकलांग हैं। आजादी बाद भी 68 करोड़ में एक करोड़ अंधे हैं । आजादी के बाद भी 2 करोड़ लोग टी. बी. के मरीज हैं, क्योंकि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता । मां के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, जिससे बच्चा अपंग हो जाता है, अंधा हो जाता है । इस देश के बारे में आप क्या सोचते हैं ।

दूसरा मुद्दा है "सामाजिक".

आज भी सामाजिक स्तर पर और जाति का नाम लेकर रोज हत्याएं की जाती हैं । भूतपूर्व प्रधान मंत्री के नाम पर आज जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है । लोगों की यह धारणा थी कि यह जातिगत भावना से और साम्प्रदायिक भावना से ऊपर उठकर काम करेगी । लेकिन क्या देखने को मिलता है ? वहां पर हरिजन छात्रों को प्रोफेसर द्वारा अपमानित किया जाता है और कहते हैं कि तुमको पेड़ से बांधकर पीटना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि दूसरे छात्र हरिजन छात्रों का साथ दे रहे हैं । क्या यह देश चल सकता है, नहीं चल सकता, न सामाजिक और न आर्थिक स्तर पर । बीस सूत्रीय कार्यक्रम की किताब मेरे पास है । आप सिर्फ हरिजन-हरिजन का नाम लेते हैं, मैं कहता हूं आप थोड़ा काम भी कीजिए । आप या तो वोट कैचिंग के लिए नाम लेते रहे और जब भी रेडियो खोला तो हरिजनों का ही नाम सुनाई दिया ।

[श्री राम विलास पासवान]

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका चाहे 20 या 25 सूत्री कार्यक्रम हो लेकिन आप एक सूत्री को पकड़ लीजिए और इम्पलीमेंट कीजिए । "एक ही साधे सब सधे, सब साधे तर जाए" ।

अगर आप एक सूत्री पकड़ लेते हैं तो आपका काम चल जायेगा । चाहे बाइबल हो, कुरान हो, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आपने तीन साल के अन्दर कितने अफसरों को सस्पेन्ड किया है और कौन-कौन सा कार्यक्रम लागू नहीं किया है । जो आफिसर्स आपके कार्यक्रम को लागू नहीं करते, उनके लिए क्या आप कोई सजा की व्यवस्था करेंगे । हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चल सकता है। लक्कप्पा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि मानेटरी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की जो दृष्टि है, वह अभी तक उल्टी है। सरकार ऊपर से कुछ करती है और भीतर से कुछ, कथनी और करनी में सामंजस्य लाना चाहिए और नीयत को साफ करके प्रशासन पर चुस्ती से कार्यवाही करके कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करना चाहिए तभी आप शोसित और पीड़ित मानव का उत्थान कर सकते हैं । नारों पर यह देश चला है, लेकिन इनसे गरीब का उत्थान होने वाला नहीं है ।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Mr. Chairman, Sir, I am proud of Mr. Lakkappa as my colleague and also as Secretary of our Party—he has been returned again—because instead of being swallowed up by the Ministry, he is able to place before the House proposition after proposition calculated to improve the working of our Government. Earlier there was a Resolution which he had moved, a non-official Resolution, to draw the attention of the Government to the need not only to prescribe but also to enforce minimum prices for agricultural produce. Now he has placed before us this Resoloution to improve the working of the 20-Point Programme and under its auspices the rural development and social development and welfare programmes for which Government has been sanctioning hundreds of crores of rupees.

I also agree with my friend, Mr. Ram Vilas Paswan, in his dissatisfaction with the way in which these things are not being worked at the grassroot level. But that does not mean that we should have only one-point programme and not 20-Point Programme. If it is only one-point programme, then you can have it only for the poorest of the poor. The other people also have got to be helped. Indeed, in recent times we have come across one clear phenomenon. Government has been paying special attention for the uplift of the Harijans. At the same time, it has been trying to improve the conditions of the backward classes also. But because the Harijans have been suppressed for such a long time, for so many centuries, by all other classes of people, including the backward classes, Government officers and then Congress people and all of us, public people and public men are repeating again and again about what we have to do for the Harijans. This has excited the ire of the Backward Classes.....

SHRI RAM VILAS PASWAN: I did not tell that you have only one point programme. I said that instead of having a 20 point programme and doing nothing, it is better that you have a one point programme and do it.

PROF N. G. RANGA: So, the Backward Classes have begun to complain now—not because nothing is being done for them but so much more is talked of in regard to what we are trying to do for Harijans. This is the difficulty in our country. So simultaneously we are obliged to cater to the immediate needs of different groups and different classes and communities in our country who are under privileged.

It is easy to criticise the Government because Government has to depend upon bureaucracy. Bureaucracy

has its own laws for its own activity. A clerk goes there, an officer goes there. Then he seems to think somehow or other that his job is done by remaining in office according to the office hours. And when any one of us, especially our poorer folk who are illiterate and who are not able to look after themselves and who are not able to fight for their own rights, when they go, when anyone of them goes to him and asks for something that the Government has offered to give to him and which it is his right to get from the Government, this officer seems to think that he is the *Ma Bap* and why should he give any of these favours to this man unless he gets something in return. This is the horrible attitude of the officers, clearks and the non-gazetted employees of the Government. Now it is easy for me to criticise them. Then they will be able to turn round and say, 'What about your politicians ? You are also playing your mischief.' This is the real difficul lty. One is competing with the other. One is undermining the other. One is discrediting the other, so much so the society to-day is now being demoralised and whatever may to the good wishes, plans and programmes of the Government , resulees are not so very satisfactory. That is one of the reasons why in Andhra, for instance, we have come to associate the Collector with the District Revenue Officer who is of IAS status and in most cases we see to it that they happen to be Harijans in the hope that these Harijans salvaged from the misery of their parents and raised to positions of power would really evince keen and sincere interest in the rank and file of their own people and help them. That kind of thing has got to be done everywhere-else throughout India.

Secondly, Collectors are associated with non-officials like MLAs, Zila Parishad Presidents and Panchayat Samiti Presidents in Andhra. I do not know what is happening in other areas. This is a very good system. Then these non-officials are impatient about the officials and *Vice-versa*. The officials are also impatient about these non-officials. If both of them are tied up in this manner. I do not think they would be scratching at each other's backs or exploit the people—they will be able to control each other and help each other also in the proper management of the funds which are placed at their disposal by the Government.

Thirdly, here is the Central Government which grants money for drought relief, flood relief, cyclone relief and then for ordinary development of employment and sanction loans, house sites and credit and all the rest of it. Then the distribution is in the hands of the State Governments. The Government of India has not got much of a control over the State Governments. One of the State Governments was so unwilling to have any kind of control from the Central Government in regard to the Food for Work that there was a regular political quarrel between them two. Now we have got to give some special thought in regard to this matter.

17.00 hrs.

Now we have got to give special thought in regard to this matter *viz.* Centre-State relations. State governments and leaders of the State parties are demanding more and more power for them; but what about the Union Government. For whose sake is the Union Government granting all this money; It is for the sake of these people. State Government is expected to cater to the small folk also but then should we not see that the State Government is controlled by the Central Government? Should not Central Government exercise its supervisory powers over the State Governments and State Governments means their administration? Thought has to be given in regard to this matter.

Sir, the other day, Mr. Gomango one of the champions of out tribal people, put a very useful question as to how the funds that are being sanctioned for the welfare of the tribal

[Prof. N. G. Ranga]

people are being utilised. Then there is another difficulty. So many Ministries at the State level are being brought in to cooperate in seeing to it that the conditions of poor folk get improved. Each department is working in an isolated manner. At the State level there is need for coordination and on top of it, the Centre has to see that this sort of coordinated effort is made in order to see that the funds are properly utilised and fully utilised.

17.02 hrs.

[SHRI R. S. SPARROW *in the Chair*]

Sir, in Maharashtra there is a scheme 'one emoloyed adult in every family' That is a good experiment which is being made. Bihar was also trying to do it but I do not know how far it succeeded. This has got to be studied. Similarly, In Andhra the Congress Government had decided, and now the present Government is continuing the policy of providing one free meal for every child everyday. How it is going to work and with what results, that has also got to be studied. Similar, is the case with rural dispensaries and sanctioning of house-sites. In Andhra, MLAs and even Ministers are competing with each other in seeing to it that every Harijan family is provided with a house-site at the earliest. Every MLA is making it his special duty to see that this programme gets implemented. It is a good move. With what results it has worked and how this can be extended to other States has to be studied.

Sir, we have been asking for social forests and also vegetable gardening. Every Harijan family is provided with a house site. All round the House three to four pumpkin plants can be one or two banana plants can be planted and in the whole cluster of houses two or three tamarind trees can be planted. This kind of social torestry has to be developed in a detailed, constructive and affectionate manner so that the total income of a housewife can be increased by 30 per cent every year. This means kind of attention to be given to the needs of these people in a truly Gandhian manner. This cannot be expected from the officers alone. This is not being provided either by the Congress people or by the friends from the Opposition at the grassroots because that atmosphere has been lost. We have to create that atmosphere once again. We can create it, provided we develop a spirit of cooperation in aiding, encouraging and propagating this 20-point programme and it is in this direction that we have got to move. One can go on adding to this list of number of directions in which the poor folk have to be helped but the two most important things are that firstly, what the middleman is doing, what a tout does, what a layer does, every public worker to whichever party he may belong, should be willing to render to these people. He should go on their behalf to the local cooperative bank, and help them; he may go to the Essential Commodities Supply Centre (whether it is Cooperative or Panchayat or Government or anything like that) and help these people to get whatever they are supposed to deserve by the Government.

For supplying essential commodities, our friend in charge of Civil Supplies here goes on saying that so many shops are being organised and so on. There are certain complaints from the Opposition that some of these things are there in the towns and townships and they do not reach sufficient number of villages. Now, we have got to see that every village gets one shop,-at least one shop. I feel there should be 3 or 4 shops so that they can compete with one another. At least one has got to be organised. But who has to organise this? Who is supposed to be the shop-keeper, cooperator or panchayatdar ? Who will do his work properly? As soon as cheap supplies of essential clothes are coming

who gets the information first? It is the local powerful man the *sarpanch* and others. They take away all the stuff by paying for this cheaply. The poor people do not get enough of it. Care has got to be taken to see that enough publicity is given in the local language papers that such and such commodities are being supplied in such and such quantity in so many centres. The announcement should be made over the Radio so that these poor folk would be able to go there. Supply must be arranged according to the Queue system, whoever comes first should get his quota.

Lastly, this Resolution is intended to strengthen the hands of the Central Government as well as the State Governments, and local Ministries. We expect them to be patriotic, also to be socialist-minded, to be Gandhian minded. We hope that Government would take necessary action in appointing, in their own way, according to their own judgment, the best possible and fully effective Monitoring Authority here at the Centre to go round the whole of India nad cover all the States, to energise the State Governments and also to bring back information as to how the money is being used or misused; and if it is misused, how it can possibly be prevented.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): माननीय सभापति महोदय, माननीय लकप्पा जी ने यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमने पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्शन होता है। जिस समय में समाज की जैसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति रहती है उसी के अनुसार साहित्य की रचना होती है। उसी प्रकार से हमारी संसद में भी जो प्रस्ताव आते हैं उनसे जाहिर होता है कि हमारे समाज में किस चीज की कमी है और उसके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिए। हम यहां पर कहते हैं कि कृषिकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन जो नीतियां आपने बनाई हैं उनका ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन हमेशा इन बातों को अपोजीशन की बात कहकर टाल दिया जाता था और उसका मखौल उड़ाया जाता था कि ये विरोधी लोग हैं इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन लकप्पा जी की तरफ से यह प्रस्ताव आए कि कृषिकों को अनाज और दूसरी उपज का सही मूल्य मिले तथा आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाए---इसके लिए एक मानिटरिंग कमेटी की जरूरत है तो इसका अर्थ यह है कि उनको भी वह बात मालूम है कि समाज में क्या हो रहा है, जिसको कि हम लोग कहते ही रहते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसका मतलब यही है कि हम जो बात कहते हैं उसको उन्होंने भी मान लिया।

हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम बनायें या एक सौ सूत्री कार्य क्रम बनायें। आप बहुमत में हैं, जो पालिसी आप बनायेंगे, उसके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारा काम है, जब वह कार्यान्वित न हो, तो हम आपको बतायें कि कहां कमियां रह गई हैं। चाहे वह किसी प्रकार का मामला है। मान लीजिए 18 परसेंट आप ने हरिजनों के लिए रिजर्वेशन करना है। अगर 18 परसेंट रिजर्वेशन पूरा नहीं होता ह, तो विरोधी पक्ष के लोग आवाज उठाते हैं कि इसको पूरा करिए। आपने बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कही है। जैसे कि व्यवस्थापिका सभा का काम है कि नीति बनाएं और न्याय पालिका का काम है कि वह न्याय करे। व्यवस्थापिका की नीतियों का कार्यान्वियन एग्जीक्यूटिव करे तो एग्जीक्यूशन आपकी पालिसी का नहीं हो रहा है। जो आप निर्णय करते हैं, वे लागू नहीं होते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कार्यपालिका का एी. एम. सबसे बड़ा हैड होता है। इससे पहले पीलीभीत के डी. एम. नहीं नहीं थीं। वे एव ब्लाक में गईं, उन्होंने वहां के एक ग्राम सेवक को बुलाया और कहा कि सौ गोबर गैस प्लान्ट की दरख्वास्तें अपने एरिए से लाओ। जब कि उसमें दस से ज्यादा गाव नहीं होते हैं और एक न्याय पंचायत के ऊपर होता है उत्तर नदेश में। डी. एम.

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

जो यह नहीं जानता कि एक ग्राम सेवक का हल्का कितना होता है। दस गांवों में सौ गोबर गैस प्लान्ट कहां से आ जायेंगे । हाई कोर्ट से किसी के मामले में स्टे-आर्डर गया है, तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं किया। यदि ऐसे कार्यपालिका के अधिकारी होंगे तो कैसे एग्जीक्युशन होगा। यह अच्छा हुआ कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां संसद में मंत्री हो कर आ गए हैं । मैं ने उनको भी बताया था और उनसे कहा है । उनको हटाने से क्या काम चलेगा । डिस्ट्रिक्ट में शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी एक एस. पी. की है और चार-चार, पांच-पांच और दस-दस हजार रुपया वे थाना नीलाम करेगा तो कैसे शान्ति और व्यवस्था कायम रह सकती है । जैसे शाहजहानपुर में हो रहा है । सारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है । आधे से ज्यादा जिलों में हो रहा है । थाने नीलाम किए जाते हैं, तो कैसे शान्ति और व्यवस्था कायम रह सकती है । एक दरोगा तो दस हजार रुपया एस. पी. को देना है तो 50 हजार रुपए की डकैती कम से कम करवाएगा तब जा कर वह हिस्सा दे पाएगा। इस प्रकार जुर्म और बढ़ेंगे । मैं इस बात को मानता हूं कि मोनिटरिंग कमेटी जिला स्तर तक जानी चाहिए । बीस-सूत्री कार्यक्रम कहता है कि भूमि का आवंटन भूमिहीनों में होना चाहिए । मैं किसी एक खास जिले का नाम नहीं लेना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं । किसी एक जिले को लीजिए । भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, यदि हुआ भी है, तो कब्जा नहीं हुआ है। मैं यह नहीं कता कि मैं बरेली का रहने वाला हूं तो आप पीलीभीप को ले लीजिए, शाहजहानपुर को ले लीजिए, बदायूं को ले लीजिए । आप किसी एक जिले का माडल बनाइए और उसकी जांच करवाइए कि सही तरीके से भूमि का आवंटन हुआ है या नहीं हुआ है । तब आपको पता चलेगा कि भूमि का आवंटन हुआ ही नहीं है । यदि हुआ है तो मोती को हुआ हुआ है या पार्वती को हुआ है । पता चला कि ये कौन है, ये जमींदार के कुत्ते और बिल्ली के नाम हैं । इस तरह से आवंटन हो गया । सीलिंग की जमीन निकली, लोग खा गये, जिस को मिलनी चाहिये थी, उस को नहीं मिल पाई । अगर कागज पर मिल गई है तो मौके पर नहीं मिल पाई है। आप जांच कर लीजिए। मैं शाहजहांपुर और पीलीभीत के एक्जाम्प्लज बना कर दे देता हूं । हम ने बीसियों शिकायतें की हैं---उन्हीं डी. एम. तक शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। फिर कैसे इम्प्लीमेन्टेशन होगा? बीस सूत्री कार्यक्रम में कैसे भूमिहीनों को भूमि मिलेगी-आप बतला दीजिये ।

श्रीमान्, अब बिजली और सिंचाई का मामला लीजिये---यह भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत है । उत्तर प्रदेश में तो अपोजीशन का कोई भी विधायक या मेम्बर पार्लियामेन्ट उस बीस सूत्री कमेटी का मेम्बर नहीं है, केवल कांग्रेस के सारे मेम्बर्स रखे हुए हैं । इस का मतलब है कि सिर्फ वे ही इस प्रोग्राम को चलायेंगे । हमें इस में भी कोई एतेराज नहीं है, लेकिन जब काम पूरा नहीं होता और हम शिकायत करते हैं तो उस की जांच करनी चाहिये ।

सड़कें बनी हैं---नये विधायक महोदय आये तो उन्होंने दूसरी तरफ से सड़क डलवा दी । जो पैसा पहले लगा था सब बेकार गया। पुल बनना शुरू हो गया था, लेकिन अधूरा पड़ा है । जहां टयूब वेल्ज बने हुए हैं---मैं अपने यहां के तुलियां और लाडपुर की बात बतलाता हूं---टयूब वैल बना है लेकिन उन को एनर्जाइज नहीं किया गया है । उन से कोई काम इनीं लिया जा रहा है । पीलीभीत जिले में जाइये---वहां पर देहात में 6 घंटे बिजली आने की बात है, लेकिन पता नहीं कब आयेगी, रात को आयेगी, दिन दिन में आयेगी, कब आयेगी । लोग तार काट-काट कर देखते हैं कि इस में बिजली है या चली गई । हमारे उद्योग मंत्री की कांस्टीचूएन्सी मेरी कांस्टीचूएन्सी से लगती से लगती है, मेरी कांस्टीचूएन्सी रुभौला तक है, उस के बाद उन की कांस्टीचूएन्सी है । वहां पता चला है कि 18 घन्टे तक निर्बाध बिजली आ रही है । यह कैसा 20 प्वाइन्ट प्वाइन्ट प्रोग्राम है ?

इसी 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में यह भी लिखा है कि जो पिछड़े जिले हैं वहां इण्डस्ट्रीज लगाई जायें। मेरे यहां पीलीभीत और शाहजहांपुर दोनों पिछड़े जिले हैं, वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई गई। इण्डस्ट्रीज वहीं लगाई जाती हैं जहां केन्द्रीय सरकार का कोई खास जहेता होगा। इस लिए मैं कहना चाहता हूं– इस का इम्प्लीमेन्टेशन सही तरीके से, समता के आधार पर हो, सब जगहों पर इस आधार पर कैसे इम्प्लीमेन्ट किया जाये, इस को देखना चाहिये।

सैंट्रल गवर्नमेन्ट का गन्ने के सम्बन्ध में केन प्राइस कन्ट्रोल आर्डर बहुत पहले से बना हुआ है। हिन्दुस्तान भर का कोई भी एक जिला मुझे बतला दीजिये जहां उस का इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है। उस में लिखा है कि जहां भी 15 दिन से ज्यादा दिनों में गन्ने की कीमत का भुगतान होगा वहां 15 परसेंट का ब्याज दिया जायेगा। क्या हिन्दुस्तान भर के किसी भी सूबे में 15 परसेन्ट का ब्याज किसानों को दिया गया है? उल्टे उत्तर प्रदेश में तो पिछले साल जनवरी तक का पेमेंट नहीं हुआ है। इस साल भी जनवरी के बाद से अब तक पेमेन्ट नहीं मिला है। इस तरह से यह केन प्राइस कन्ट्रोल आर्डर रद्दी की टोकरी बन कर रह गया है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे किसान को खुश करेंगे? यह तो सारा इम्प्लीमेंटेशन का काम है।

आप किसी भी जिले में चले जाइये और देख लीजिए कि शिक्षा की क्या दुर्गति है। आप शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत। लेकिन शिक्षा का हाल यह है कि टीचर स्कूल में महीने में दस दिन भी नहीं जाता। श्रीमन् मैं अपने क्षेत्र में एक जगह गया। शारदा नदी पर धनाहराघाट के पुल के पास एक गांव में मुझे बताया गया कि सामने जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है लेकिन उसमें जुलाई 1980 से लेकर 26 जनवरी, 1981 तक न कोई टीचर आया, न कोई बच्चा आया और न कोई आदमी आया। 26 जनवरी को भी स्कूल बंद पड़ा था। 26 जनवरी को झण्डा फहराने के लिए हैड मास्टर आये थे। उस स्कूल का एस.डी.आई. दो बार मुआइना कर चुका है और उसने स्कूल को ठीक तरह से फंक्शन करते पाया। यह है आपका ट्वन्टी प्वाइंट प्रोग्राम।

मैं चाहता हूं कि इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए एक कमेटी बननी चाहिए।

कल यहां बालाहार का सवाल उठा था। मैं और प्रदेशों के बारे में तो नहीं जानता, उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। मैंने वहां स्टडी की है और पाया है कि पिछले बाहर मास में किसी भी बच्चे को एक पैसे का भी बालाहार नहीं मिला है। ईंधन के लिए, रसोइये के लिए, दूध के लिए पैसा मिलता है, लेकिन सब बाजार में ही रह जाता है, किसी बच्चे तक नहीं पहुंचता। आप किसी एक ही चीज को पकड़ लीजिए और देख लीजिए कि उसकी क्या प्रगति हो रही है।

श्रीमन् एक स्कीम आपने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जोब देने की बनायी थी। स्वास्थ्य विभाग में सी. एच. डब्ल्यू. जैसे छोटे से वर्कर को रखने की बनायी थी जिसको कि आप 50 रुपये माह तनख्वाह देंगे। उसमें क्या हो रहा है? पीलीभीत में उस पचास रुपये माह की नौकरी के लिए डाक्टर और सी. एम. ओ. पांच-पांच हजार रुपये अपोइंटमेंट के समय लेते हैं जबकि आपके आर्डर में लिखा है कि जिसको प्रधान रिकमण्ड करेगा उसको तो आप को रखना ही होगा। जो रिकमण्ड नहीं किये गये हैं, उनको भी नौकरी में रख लिया जाता है और उनको आठ दिन ज्वायन करा कर, फिर उनको निकाल दिया जाता है। आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लोग मनचाहे लोगों को रख रहे हैं। इसके बारे में मैंने डी. एम. से शिकायत की तो उसका मुझे कोई जवान नहीं मिला। इसलिए मैं बराबर यह कहता आ रहा हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।

आर्म्स लाइसेंस की बात को ही ले लीजिए। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली जिलों में आर्म्स लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं और पिछले एक साल से नहीं दिये जा रहे हैं। फिर लोग डकैतों से कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? लाइसेंस देना जब चाहे जिला अधिकारी रोक देते हैं और कहते हैं कि हमको रोकने के लिए कहा गया है। उनके पास लिखित में कुछ नहीं है।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

हमारे यहां 61 वर्ष का एक मिनिस्टर है । उसने एक साल में 60 उद्घाटन किए हैं । इसलिए मैं आप से कहता हूं कि अगर आप अपने बीस सूत्री कार्यक्रम का ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो सब से पहला काम तो आप यह कीजिए कि अलग से डी. एम. और एस. डी. एम. को डिप्यूट कर दीजिए जो कि मिनिस्टरों को लाएं, ले जाएं । वरना आपके सारे काम दरहम-बरहम हो जाते हैं । मेरे जिले में एक दिन दस मिनिस्टर आ गये । उस दिन न डी. एम. का पता लगा, न एस.डी.एम. का पता लगा, न एस.पी. का और न डी. एस. पी. का पता लगा ।

अन्त में मैं श्री लकप्पा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हें इस बात का दर्द है कि देश में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है । उनका जो संकल्प है कि इम्प्लीमेन्टेशन के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बिठा कर देश की प्रगति को आगे बढ़ाना चाहिए इसमें मैं उनके साथ हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं लकप्पा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । भारत सरकार और राज्य सरकारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वे ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनके संबंध में मानेटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । यह नितांत आवश्यक है । जितने भी कार्यक्रमों के इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लानिंग मिनिस्टर को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री भी इस बात को चाहती हैं कि इस देश में जो गरीबी की सतह से नीचे के लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास जल्दी से जल्दी हो और उनकी आवश्यकताओं की शीघ्र पूर्ति हो । उनको सारी सुविधाएं ठीक प्रकार से उपलब्ध कराई जाएं । जब हमारी प्रधानमंत्री चाहती हैं, हमारे मंत्री महोदय चाहते हैं तो फिर रुकावट कहां आती है । सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ।

लैण्ड रिफार्म का कार्यक्रम लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने यह बहुत अच्छा कार्यक्रम हमको दिया है, इससे बहुत लोगों का भला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन कई जगह पर गड़बड़ी भी हुई है । इस कार्यक्रम को अगर और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के इंप्लीमेंटेशन के बारे में जो मशीनरी या ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में है, वह इसको ठीक तरह से इप्लीमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, देश की या प्रांतों की सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है इसको देखने की आवश्यकता है । मैं अपनी स्टेट के बारे में बता सकता हूं । वहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम के इंप्लीमेंटेशन के संबंध में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें भी बहुत पक्षपात किया गया है । उस कमेटी में इस प्रकार के लोगों को रखा गया है, जिनका बीस सूत्री कार्यक्रम से कोई ताल्लुक नहीं है । किस तरह से इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा ।

गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने लैण्ड रिफार्म शुरू किया। लेकिन यह कार्यक्रम कई जगह इस कदर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया है कि बड़े-बड़े जमीदारों को जमीनें दे दी गई हैं और इस कार्यक्रम को बिगाड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है । आज इन लोगों की वजह से हालात खराब हो रहे हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन तो आपने दे दी, लेकिन क्या आपने उस गरीब को साधन भी दिए हैं, जिनके जरिए वह अपनी जमीन को जोतकर अनाज पैदा कर सके । आपके नेशनलाइज बैंक पैसा देते हैं और आप सबसिडी देते हैं 33 परसेंट । 3000 रुपए में एक हजार रुपया सबसिडी होती है, लेकिन वह एक हजार रुपया किसकी जेब में जाता है । वह एक हजार रु. बैंक मैनेजर, विकास अधिकारी,

या जो अधिकारी जमीन के संबंध में जानता है, इनके बीच बंट जाता है । इसलिए इस कार्यक्रम पर मानेटरिंग की आवश्यकता है । यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। जब तक इस प्रकार की मानेटरिंग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा । बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था क्योंकि उस वक्त पैसा पूंजीपतियों को मिलता था, वह पैसा गरीब किसान और मजदूर को मिले। प्लानिंग मिनिस्टर साहब आप इस बात को देखें कि उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है ताकि व्यवस्था कुछ ठीक हो सके ।

सीलिंग के सम्बन्ध में मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपने जागीरदारों और राजा-महाराजाओं के ऊपर सीलिंग लगाकर जमीनें लीं । उन जमीनों पर आज तक कब्जा नहीं दिया है। कागजों पर अलाटमेन्ट हो गई है लेकिन तलवार और बन्दूक वाले आज भी गरीब को जमीन के पास पहुंचने नहीं देते । कई हत्याएं, डकैतियां और मार-पीट उनके साथ होती है । इस प्रकार के हालात को देखने के लिए जब तक आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश की प्रधान मंत्री ने कहा था कि इन गरीबों की मदद करने के लिए कोर्ट्स बनाओ और उनकी सहायता करो, जो बदमाश हैं उनको सख्त से सख्त सजा दो । वह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाया और न ही गरीबों को राहत मिली । जो जमीनें आपने अलाट की हैं, उनका अवश्य उन्हें कब्जा मिले और उसके बाद प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए ताकि कोई भी बदमाश आदमी उन्हें तलवार और बंदूक से भगा न दे और जान से न मारे । जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए तब कहीं सामाजिक और आर्थिक उत्थान ठीक से हो सकेगा। मैं समझता हूं मानिटरिंग की सख्त आवश्यकता है, इस ओर प्लानिंग मिनिस्टर अवश्य ध्यान दें ।

आपने एक कार्यक्रम आइ.आर.डी.पी. "इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंद प्रोग्राम" चालू किया है । आप यह चाहते हैं कि गरीब लोग स्वयं छोटा-मोटा धन्धा शुरू करके अपनी गरीबी को दूर करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में भी वही घपला है जिसके बारे में मैंने कहा कि बैंकों में गड़बड़ी हो रही है । भेड़ों के लिए, बैंक के मैनेजर, विकास अधिकारी जानवरों के डाक्टर द्वारा जो सब्सीडी दी जाती है उसमें भी गड़बड़ी होती है। इस ओर भी खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है । यह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमारे देश की नेता ने इसको चलाया है ताकि जो 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अपना रोजगार शुरू करके अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें । मगर जो ब्यूरोक्रेसी यहां बैठी हुई है, वह इसको ठीक तरह से इम्पलीमेंट करने में योगदान नहीं दे रही है। हमारे किसी भी अधिकारी के दिल और दिमाग में यह भावना नहीं है कि हमारे देश में कितने भूखे-प्यासे हैं जिनके बाल-बच्चों के लिए कोई सहायता नहीं है बल्कि ये अधिकारी लोग उनका खून चूसने में लगे हुए हैं । उनके संबंध में आपको विशेषतौर से सख्ती तब जाकर व्यवस्था ठीक हो सकेगी । ताकि कोई भी आदमी गड़बड़ी न कर सके लिया है, उनको अवश्य सजा देनी चाहिए से कार्यवाही करनी पड़ेगी । जिन लोगों ने गरीबों के हक को मारकर पैसे को जेब में रख

आज हमारे देश में 2 लाख 40 हजार ऐसे गांव हैं जिन्हें प्राबलम विलेज कहा जाता है यानी जहां पीने का पानी नहीं है । राजस्थान में आज 24 हजार गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी नहीं है । वे लोग दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मील से पानी लेकर आते हैं । कहीं-कहीं पर तो ऐसा पानी है जहां लोग अन्धे हो जाते हैं या दूसरी कोई बीमारी लग जाती है या जान से भी मर जाते हैं । आप हर साल पैसा देते हैं कभी 20 और कभी 25 करोड़ । चार-सौ या पांच-सौ गांवों में पैसा मिलता है लेकिन उसका उपयोग बहुत गलत तरीके से हो रहा है । राजस्थान विधान सभा में लोगों ने इस बात की शिकायत की कि भारत सरकार ने या इन्दिरा गांधी की सरकार ने जिन गांवों के लिए पैसा दिया वहां पर पानी मुहैया कराया जाए । लेकिन ऐसी मशीनरी बैठी हुई है कि इस पीने के पानी

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

के पैसे का भी दुरूपयोग हो रहा है । वहां पर इस बात का भी आरोप लगाया गया था कि जो ट्यूबवैल्स और हैन्ड-पम्प लाए, उनका 80 फीट पाइप पहुंचा लेकिन पैसा 180 फीट का लिया । और ऊपर जो प्लेटफार्म बनता है 280 रु. में उसके बजाय 1,200 रु. लिये गये । इस तरह की जो गड़बड़िया हैं, जिन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सामाजिक उत्थान के लिए अगर ऐसे कार्यक्रमों में गड़बड़िया होती हैं तो हम देश के साथ गद्दारी करते हैं । ऐसी गड़बड़ियां जहां भी हों उनकी मानीटरिंग होनी चाहिये और जांच करानी चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस पैसे का दुरूपयोग करके लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में बाधा पहुंचा रहे हैं ।

सभापति महोदय : समय बहुत थोड़ा है और जो सदन ने तय किया था वह पूरा हो चुका है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : और बढ़ा दिया जाये समय।

सभापति महोदय: वह मैं पूछ लूगां। 4 घंटे इसके लिये दिया गया है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं क 2 घंटा समय और बढ़ा दिया जाय ।

सभापति महोदय : वह बाद में करेंगे। सबजेक्ट तो बहुत बड़ा और इम्पोर्टेन्ट है, मगर टाइम का ख्याल करते हुए, दूसरों को भी बोलना है, मंत्री जी को भी बोलना है । अगर हाउस को पूछना पड़ेगा तो वह काम और भी गम्भीर हो जायेगा। इस वास्ते कृपा कर के पाइंट बता दें, रिपीटीशन न करें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वितरण का कार्यक्रम मुस्तैदी से लागू होना चाहिये । कोआपरेटिव सोसाइटीज बनानी चाहियें जो इन चीजों को बांटें और इसके लिए सरकार को पैसा देना चाहिये क्योंकि बिना पैसे के कोआपरेटिव सोसाइटीज नहीं चल सकतीं । इसलिये जब तक कोआपरेटिव सोसाइटीज इकोनामिकली वायेबिल नहीं बनायेंगे तब तक वितरण का काम नहीं चल सकेगा ।

जो लोग विलो पावटी लाइन और बैकवर्ड हैं उनके संबंध में विरोधी दल के लोग बहुत प्रचार करते हैं । मेरा कहना है कि जो भी आर्थिक तौर से कमजोर हैं चाहे शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का हो, या बैकवर्ड हो, चाहे ब्राह्मण, जाट हो, अगर वह इकोनामिकली बैकवर्ड है तो उसको सारी सुविधायें मिलनी चाहियें । अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब कलेक्टर बन गया या पूंजीपति बन गया तो उसके बच्चों को इस प्रकार की सुविधायें देना उचित नहीं है । इसलिये आर्थिक तौर से जो पिछड़े हुए हैं उनको वह सारी सुविधायें मिलनी चाहियें । जो पूंजीपति हैं, या ब्लैक मार्किटिंग करते हैं, स्मगलिंग या होरडिंग करते हैं और दूसरों का हक मारते हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये और उनको पकड़ा जाना चाहिये । इस व्यवस्था को मजबूत किया जाय तभी सामाजिक और आर्थिक उत्थान ठीक से कर सकेंगे ।

हमारे राजस्थान में बिजली की बहुत कमी है । पिछले साल भी नहीं मिली और इस साल भी नही मिल रही है । बड़े-बड़े कारखाने बन्द पड़े हैं । वह कह रहे थे कि किसान को 8 घंटे बिजली मिलती है । हम तो कहते हैं कि 4 घंटे भी नहीं मिल रही है, किसान बरबाद हो रहा है, सारी इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं । इसलिये सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बिजली किसान और कारखानों को मिलनी चाहिये तब जा कर मजदूर और किसान आर्थिक तौर पर सम्पन्न हो सकेगा ।

इसी तरह से हैवी इंडस्ट्रीज ऐसे क्षेत्रों में लगनी चाहिये जो बहुत बैकवर्ड हैं । उन बैकवर्ड प्लेसेज में अगर हैवी इंडस्ट्रीज लगायेंगे, बड़े-बड़े कल-कारखाने लगायेंगे तो उनसे लोगों को एम्पलायमैंट मिलेगी और लोग आर्थिक तौर पर सम्पन्न हो सकेंगे ।

मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे ।

एजूकेशन के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं । हमारे भाई राम विलास जी ने बहुत ठीक कहा कि जब तक पब्लिक स्कूल एबालिश नहीं होंगे, तब तक समानता नहीं आ सकती । बड़े आदमी का लड़का इन पब्लिक स्कूलों में पढ़कर कलेक्टर और बड़े-बड़े अधिकारियों का स्थान लेगा और गांव के जो बच्चे हैं, जिनके पास न सलेट है न पैंसिल है, न बैठने के लिये स्थान है वह तो छोटे-छोटे स्कूलों में पढ़कर पटवारी या मास्टर से ज्यादा नहीं बन सकता है । इससे ज्यादा आगे वह नहीं जा सकता है । यह अन्तर तभी मिट सकेगा जब सब को समान एजूकेशन मिलेगी ।

हैल्थ के बारे में भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज लाखों आदमी अन्धे हैं, कैंसर से बीमार हैं, उनकी बीमारी के इलाज का कार्यक्रम जब तक बहुत बड़े पैमाने पर हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार अपने हाथों में नहीं लेगी तब तक आर्थिक और सामाजिक सम्पन्नता की बात जो हम करते हैं, वह वह नहीं आ पायेगी । इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इसे हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में लिया है, उसके इम्पलीमेंटेशन की आवश्यकता है । आज गांव में डिस्पैंसरियों में दवा नहीं मिलती है, कोई साधन उनके पास नहीं है । ऐसी साधनविहीन व्यवस्था के जरिये हम देश में इस उत्थान को नहीं ला सकते हैं । इसलिये इसे मोनिटरिंग करने की बहुत आवश्यकता है । अन्त में मैं लकप्पा जी के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का जो प्रस्ताव है, उसका दिल से समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : आनरेबल मेम्बर्स से मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि जो टाइम आपने स्टिपुलेट किया है, उसके हिसाब से चलना चाहिये । जो साहब बोलें, वह थोड़ा टाइम लें, अपने प्वाइन्टस का रिपीटीशन न करें। प्वाइन्टस दिए जाने चाहिए, मगर उनको एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है । इसलिये मेरी विनती है कि आप इसका ध्यान रखें ।

मैं एक रिक्वैस्ट और करना चाहता हूं कि जो टाइम तय किया गया था, वह खत्म हो गया है । अब आप चाहें तो इसको और एडवांस कर सकते हैं । कितना टाइम और चाहिये ?

एक माननीय सदस्य : इसे साढ़े 6 बजे तक खत्म किया जाये ।

सभापति महोदय : मेरे ख्याल में इसे सवा 6 बजे तक कर दें । इसमें मिनिस्टर भी बोलेंगे और एक दो मेम्बर भी बोल सकते हैं और रिप्लाई भी होना है ।

एक माननीय सदस्य : ठीक है ।

सभापति महोदय: श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग): सभापति महोदय, इसके बाद जो दूसरा प्रस्ताव आना है, उसको मूव करने का अवसर तो मिलेगा?

सभापति महोदय: इसी लिये हमने सवा 6 बजे का टाइम फिक्स किया है ।

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): I am thankful to you for having called me to speak.

17.44 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Lakkappa has brought this Resolution which has provided as it were a platform on which Members of Parliament irrespective of party affiliations, have assembled and spoken with one voice. If I may say that the Members of the ruling party have been more vocal in highlighting the deficiencies in the implementation of the programme, I would not be wrong.

As you are aware, we are committed to the establishement of an egalitarian society in our country.

When we embarked upon planned development of the Country, in every Five Year Plan the emphasis was on reducing the disparities in the Society. Now, after 35 years of our planned development phase, we have noticed that instead of reducing disparities, the disparities have widened, distortions have arisen and everybody is feeling that instead of going towards the goal, the goal itself is receding from us. There is need for vigorous efforts on the part of all of us, I should say, for implementing the programme with speed because tardy implementation of these programes have created all these problems which are very serious. There is no dearth of programmes and a number of programmes have been given in all the Five Year Plans. We have had programmes but unfortunately the implementation has not been satisfactory, has not been done with the same speed which was intended, with the result that now Mr. Lakappa has brought forward this Resolution to say that there is a need for a committee to monitor the programmes for speedy implementation of these programmes-socio-economic programmes. It was expected that after freedom, it was our obligation to transform the society, the socio-economic structure of the society and we just did try but it could not be done. The condition of the society is very unsatisfactory. You were not here, Mr. Chairman. Just now, my friend Mr. Girdhari Lal Vyas has very eloquently spoken about the way these programmes are being implemented and how leakages are taking place and why the fruits and benefits of these schemes are not reaching the poor. You will notice that almost 50 per cent of our population is below the poverty-line. We have been talking about land reforms right from the very beginning but, as myf riend Mr. Ram Vilas has pointed out, after all this we have been able to distribute only 17 lakh acres of land. It has bred lot of discontentment in the rural areas. The scene is most frightening, I should say, and every day some kind of clashes are taking place for minimum wages, over the cultivation of land, etc. If I may say, Mr. B. K. Nehru, the other day in his speech, doubted the claim of record output on food front. He said that there has been a slowing down of the rate of agricultural growth. He said that the reasons are perhaps that in some parts of the country, absentee ownership of large tracks of land continues, and that the kind of breakthrough that scientists have made in wheat and rice, has not been in other crops and possibly that we are once again not allowing the agricultural prices to rise to an appropriate level. This is an observation made byr Mr. B. K. Nehru, by an experienced, able and respected administrator and from which you can see that all our claims for major land reforms and surplus foodgrains are not bieng accepted.

The objective conditions prevailing in the society confirm the observations made by Shri B.K. Nehru. Therefore, it is high time that we sit together to find out where is the snag, what is the obstacle in the way of implementing the land reform measures.

We have not been able to bring the panchayats into the picture. Therefore, we are not able to identify the lands owned by the landlords. That is why, as my friend, Shri Gangwar, has said, some lands are allotted even in the names of cats and dogs, which are pets, by the landlords because there is no local man associated with the work who can see through it and the officers are not interested in finding out the truth of it. Therefore, we are not able to lay our hands on the surplus lands which we can distribute.

Therefore, there is need for some kind of a body to overs-see the implementation of these programmes. The setting up of a body at the Central level alone will not do. In fact, at the Centre we have a body in the

Planning Commission, the Programme Evaluation Organisation, which goes round the country and makes evaluation and a report. But from that report we cannot get a correct picture. The correct picture has been brought before the House by several hon. Members, who have spoken on this Resolution. Even our venerable friend, Professor Ranga, said, the results are not satisfactory. He cited the example of Andhra, where the Collector and the public workers sit together and try to oversee the implementation of these programmes.

Much has been said about the 20-Point Programme. We all like that programme. But the difficulty is that it is not being properly implemented. I am not the only person to say that; even the Congress members have said it. If really mean business, then the implementation committees that you set up at the district level must contain representatives of all the political parties. The 20-Point Programme should not be treated as a Congress Party programme; it should be treated as a national programme and the representatives of all political parties in the area should be associated with the implementation committee. Now there is preponderant representation for the Congress with one or two members of the opposition in the implementation committee. As Shri Gangwar said, the result is that many of the schemes are sanctioned for those areas from which the Congress members come and the other areas are neglected. So, there is no harmonious development. This Resolution of Shri Lakkappa serves the very useful purpose of highlighting the difficulties in the way.

In the budget speech the Finance Minister has stated that he wants to curb ostentatious living to create a climate of austerity. I think this is the need of the hour. If you are not going to impress upon those people who are suffering from privations that you are also living an austere life, it will be adding fire to the discontent in the hearts of those people, which will create a volatle situation, an explosive situation, in the society. Therefore, there is a need for this.

By the fiscal measures it should be possible for the Government to curb ostentatious living and stop this kind of wasteful expenditure. They should tap the unaccounted wealth. Since there is a lot of evasion of tax, the asdministration has to be geared to check this. Then only you will be able to ensure that the people who are making a lot of money and spending it only on luxuries are prevented from doing so And a situation sh ould be created or a climate should be created which should inhibit them from doing this kind of a thing. Even with regard to Green Revolution, we know what has happened ultimately. The rich people have got capital and lands, and distributive justice again is relegated to the background and you find that there is a great hiatus growing in the society between the haves and have-nots. So, this is a problem which has been existing during the last 35 years of our planned development and it is time that we sit together and take it as a national programme and see that all these programmes are implemeted in right earnest so that the disrortions that have grown in the society are controlled and the disparities that are growing are narrowed down.

What is the position today ? Ten per cent of the top people are in possession of 50 per cent of the wealth while 10 per cent who are at the bottom are getting about

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

Rs. 80 a year. That was the figure given in 1977. Then, the unemployment problem also is becoming acute. The other day the Prime Minister while replying to the Motion of Thanks on the President's Address said that it will be possible for the Government to bring 17 million families above the poverty-line. But how many people are below the poverty line ? The Government has not said anything about this. There is going to be an exercise in defining those who are unemployed. By definitions you will not be able to feed the people or you will not be able to satisfy the people. You should take the real conditions that are obtaining and decide what you should do so that the benefits of the planned development reach the common people of this country. Therefore, in this respect I wholeheartedly support the Resolution moved by Mr. Lakkappa and suggest that there should be a Committee at every level consisting of representatives of all parties and it should create a feeling that this is a national programme, not a party programme. But this 20-point programme is being sought to be done like that. It will be possible then to monitor the implementation of these programmes and see that those infirmities which have crept in because of which these distortions have arisen and because of which the implementation of the programmes has become tardy, has not been done with speed, are removed. Then those conditions will desappear and people will be made to work in a proper spirit. The situation in the country today is, as I said, explosive and warrants a high priority action to deal with it and unless the Government shows to the nation its earnestness to do it, I think the situation will gradually deteriorate and go beyond our control.

So, once again I commend this Resolution to the Government and I hope that all parties will be associated with this measure.

SHRI R. Y. GHORPADE (Bellary) : Mr. Deputy Speaker, Sir I must congratulate my friend, Shri Lakkappa, for having moved this all comprehensive Resolution not only stressing the importance of this economic programme but also drawing the attention of all concerned regarding its implementation. This is the crux of to-day's national problem. Every section of the population in general and the weaker and poorer section in particular in our country to-day feel that there is a big gap between intention and implementaiion. It has been very much the desaire of our Prime Minister to focus the attention of all concerned on this National 20-Point Programme time and again. My colleagues on the other side should also realise that the 20-Point Programme is no longer a Congress Programme but a National Programme to uplift the weaker sections in every region. Hence the Prime Minister has been again and again reiterating this to all concerned. Even lately I saw in the Press that the Prime Minister has written to all States, irrespective of whoever rules them to consider the 20-Point programme, as a National Programme, and to implement the same with speed. It is once again because of her deep concern to the weaker sections of the country in every region that she would like the implementation of these programmes to be taken up on a war footing.

I an sure, Shri Lakkappa must have made such attempts earlier in his long tenure of 25 years as a Legislator, to focus the attention of all concerned for the implementation of such programmes. Any way in my short tenure of three years in Parliament, I have failed to make the concerned authorities realise the importance of speedily imple-

menting these programmes in order to bring economic prosperity to the doorsteps the weaker sections as dsired by the Prime Minister—may it Ministers, Chief Ministers or Senior Civil Bureaucrats at the State or District level. Here I would like to stress that I have nothing personal against any of the above authorities. Shri Chavanji may be to day occupying the Minister of Planning and to-morrow he may occupy some other portforlio. Hence it is not only the concern of the Minister in charge of the portfolio but also the concern of all of us to speedily implement this laudable National Progrmme. I personally feel very strongly that it is a crime that this National Programme is not being implemented with the necessary speed and concern in order that the fruits of thesprogrammes reach the doorsteps of the common man. What is the use of passing this Reslution ? What is the use of these 20 Point Programme if ever the last 35 years, many of these programmes had not reached the doorsteps of the weaker sections in an appreciable manner for various reasons. Truth must be spoken at this forum; otherwise these programmes will remain only as a dream or a platform talk or only on paper, if the tremendous gaps are not narrowed down.

I may again repeat that I have failed to make the Ministers, the Chief Ministers and the concerned authorities to understand the seriousness of the implementation of this people's programme with the necessary speed. I am speaking from this side of the Banch and am saying this as my solemn duty to the people to the House. I and to my colleagues. The blame is not to be put on one section or the other. I believe in the saying

"यथा राजा तथा प्रजा."

The politican has to be blamed. irrespective of the party to which he belongs to. It is his non-performance which matters. I must remind my good friend, Shri Ram Vilas Paswan, that whenever the Opposition has ruled, they also have shown scant regard to these developmental programmes meant for the common man. These programmes are National Programmes. We must, irrespective of the party to which we being, essert and fight for the implementation of these national, developmental programmes. This our solemn duty to our people. These are programmes meant for the poorest among the poor. There are bureaucrats and bureaucrats. There are many of whom, the Nation is proud of. They have admirably served the administration of this country over the years but there are also many bureucrats who are not at all concerned about the welfare of the people. They are also our brothers. They are not from England or Japan, but they are all part of our system. Unfortunately, they have not changed their attitude. I have said in the earlier sessions that the white saheb has left this country but unfortunately the brown saheb has taken place. He is far away from the feelings of common man. He does not feel for them as his own brothers and sisters. His attitude is that of a Britsh officer. Some time I feel, that this word "Sahab" should be removed even in the day-to-day usage. The "Saheb" has gone into the heads of many of the officers and they think they are the masters, because once upon a time this word "Saheb" was synonymous to the concept of Master servant relationship. I personally feel that this Master attitude is doing the maximum damage.

For example, I would like to bring one more aspect to justify my above observation—you may ask any Member of Parliament irrespective of any State to which he belongs, whether Heads of De-

[Shri R. Y. Ghorpade]

partment or Secretaries have visited the District Headquarters and physically verified the impact of implementation of these programmes. I am confident that the answer will be "No". By chance, if such Senior officers had visited the District, they confine themselves to aircondition Tourist Bungalows or Inspection Bungalows which are beautifully furnished particularly, the Tourist Bungalows where discussions are held and paper figures are obtained without any attempt to go down to the project sites or where people's programmes are being implemented. One should assess at all levels as to how much of these development programmes have been implemented Statewise. Take for example, the Borewell—How many borewells have been sunk? How many of them are in working condition and how many have ceased functioning and the reasons for the same. I would like the Honourable Minister to take note that unless these physical verifications take place periodically, we will never know the correct position. Even a small trader assesses once a year not only his profit or loss but makes a physical assessment of his commodities that he is dealing with in order to assess the condition of these commodities and whether they should be disposed of or carried forward to the next user or season. In the last 35 years, I would like to know whether such a phyiscal assessment took place as far as the various programmes are concerned and whether Govt. is aware of the correct situation. When I say 'assessement', it in not the 'assessment' that is made in sitting in air-conditioned offices and guest-houses but going to the field and getting the actual figures.

Coming to the last point, I do not want to travel over the same aspects as other Hon. Members have spoken on.

MR. DEPUTY SPEAKER: You want to revolutionalise the administrative system in our country.

SHRI R. Y. GHORPADE: Yes. But it is not by words but by action.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East): He wants to normalise the administration which is now abonormal.

SHRI R.Y. GHORPADE : There is nothing like normal or abnormal. We are all normal. It is only the attitude which I would like the concerned authorities to change. I for one, strongly feel that the Politicians must change, his attitude first and then buraucrat will automatically change. If ruler changes his attitude, automatically his subordinates will change their attitude. This is what I am trying to say. I blame myself first. The politicians have to be blamed first and no one else.

We all talk of economic development and its implementation. The largest section in this country is the Farmer—which consists of different classes and community. The Indian farmer by and large is not Raja or Maharaja or a Kulak. In fact we have borrowed this word from the foreign dictionaries. The farmer is made up of Harijans, Vysyas, Kshatriyas and for that matter of fact, of all communities. A farmer is the hardest hit now-a-days. We talk about uplifting of Harijans and this section or that. I feel these talks are merely to divert the attention. In fact after a number of years after Independence, all these phrases are outdated. What is most important is to raise the level of all sections of the people who are below a particular economic level. Terminologies will not solve problems and that is why the Hon. Prime Minister gave to the nation the 20-point Economic Porgramme which is not only a National Programme to raise economically the standard of all sections of people without distinction of caste, colour or creed.

Why I have raised this aspect ? The other day our Finance Minister

talked about levying taxes on Poultry Farms, which I understand, are doing well of late. The moment one section of the former is a little well-off, we see, everyone's eyes focussed on him, but when it comes to industrial sector, small, medium or large, the attitudes are different. For example. if an industrialist proposes or engaged in export-orie ted production, he gets a long list of benefits consisting of concessions, subsidies, loans, income-tax holidays, rabates etc. but when it comes to a farmer, the attitude is different.

When so much concessions could be given to an Industry, i.e. export-oriented, why could not the same attitude be shown towards the farming sector ? For example, if the Poultry farms are doing well why don't you encourage them to export their product either in a direct form or in an indirect form and thereby Govt. can earn foreign exchange. Why to kill the goose that lays the Golden Eggs when it comes to farming sector.

Sir, you know Coffee and Tea are exported, to a large extent. At the same time over the last ten years if not more the internal market has been stable because the Coffee producer makes his extra from the export and does not tax the Indian consumer. Why the same rule is not applied other farming sector. When already the Plantation sector has shown that exports have brought great stability to the industry. At the same time I must draw the attention of the House that even in the Plantation Sector, no concessions are given as is given to the industrial sector when they export their commodities.

The time is overdue when the authorities should change their attitude towards the farming sector and make the Indian farming export-oriented. We have a ready market in and around Middle East and many of our neighbouring countries.

Today-, we here of Sugar glut, because last year, the prices of sugar were remunerative. If we do not have a market for a Commodity in its present form, we just find ways and means of converting it into some other form which will attract export. For example, Ragi is grown in large areas in Karnataka. Western countries do not consume Ragi in its present form but if it is exported as Ragi Malt, there is a great demand for the same.

As I am on this subject, I would like to go on record that unless we give a parity price to the former, there is no future for the farming community and secondly, we must have an export-oriented attitude towards farming produce, if we re lly inted to economically strengthen the farmer.

I support Shri Lakkappa's Resolution, if we really want to implement the socio-economic programmes speedily.

In conclusion, I would like to make the following observations:—

Firstly, there should be an honest desire on the part of politicians to implement this programme.

Secondly, the State and National Programmes and Projects should be implemented in a time-bound manner.

Thirdly, the non-performing politicians and bureaucrats who have failed to implement people's programmes and who have a stronghold on the Govt. should not be entertained. This holds good to all parties and all Govts.

Lastly, I have always been advocating the concept of accountability, may it be the politicians or bureaucrats.

If we do not hold the Politicians and Bureaucrats accountable, I am afraid these laudable People's Programmes will

[Shri S. B. Chavan]

by and large will remain on paper. Hence I would like the Honourable Minister to give his serious thought to this aspect. Further, the Honourable Minister should at least choose one district from each State as a Pilot district and go into all these aspects in great detail and assess the various lacunae and shortcomings for implementing the development programmes, at the village level. If we start implementing these programmes on a war footing successfully in a district, thereafter, we can launch a National Implementation Programme, which is the need of the hour.

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): Sir, Mr. Lakkappa has moved a very simple resolution which has aroused a tremendous amount of response from all sections of the House and almost all the administrative Ministries in the Centre and in the States have figured during the discussion. It looked as though this is a sort of general discussion on the Budget which has been going on.

I think that the time at my disposal is going to be so short that it is impossible for me to respond to all the points which have been raised. I have taken note of most of the points which were raised but my primary responsibility is to respond to what Mr. Lakkappa, my friend, has put forth as a very innocent kind of suggestion that this is a kind of monitoring argument that he would like to go in for. I have heard his speech very patiently and I was trying to find out what exactly Mr. Lakkappa has to convey through this resolution.

Most of the Members seem to be unanimous on this point that there is nothing wrong in the policies and programmes which have been formulated by the Central Government. They have some example or the other, to point out that at the stage of implementation these are the distortions which we come across. And if I have understood them correctly, Mr. Lakkappa started it and some of the other Hon. Members also blamed the bureaucracy and said that it is the bureaucracy which has to be held responsible. One Hon. Member even went to the extent of saying "You please take note of this and let us know as to what action has been taken against the officers who have failed in this matter." I believe it was the Hon. Member Shri Ram Vilas Paswan. It is a very strange coincidence that when we were discussing the Punjab situation, everybody was talking in terms of more autonomy for the State Governments and now when Mr. Lakkappa's is being talked about, it is the other end which the Hon. Members are going on saying that "No, no. These are matters which are dealt with at the State Government level but at the lowest level we must have some say in the matter."

I do not hold any brief for either the bureaucracy or even for that matter some of the politicians. I fully agree with Mr. Ghorpade when he said that among the bureaucrats you will come across people who are very much committed to this programme and like dedicated workers, you will see these officers going to the villages to implement the programme in the spirit in which it has been announced by the Prime Minister.

I am also aware of some of the officers who are trying to delay matters, harass some of the beneficiaries and, as some of the Members have pointed out, though Government takes satisfaction in the fact that we have provided for subsidy, the subsidy amount does not reach the beneficiaries. I do not know what will be the reaction of the Hon. Members if I were to say that if subsidy is the cause of all the distortions that we find in the implementation, let us completely give up the subsidy. Subsidy has to be continued and hon. Members would like to have some say at the stage of implementing a particular programme!

Bureaucrats have been having some traditions and the Personnel Department which is also it charge of administrative reforms has been having different courses for reorientation. Officers are given reorientation courses from six weeks to almost eight to nine months depending upon the type of course which they are conducting. I happen to be the Chairman

of one of the Institutes here, the Indian Institute of Public Administration, IIPA, where the courses are being conducted for all the officers right from Joint Secretaries downwards, and officers from different areas come over here and they are given complete re-orientation about their attitude, the spirit of the Constitution, and the way they are supposed to implement the dicerent programmes of the Governenmt. But in spite of all that, there is no escape; I cannot possibly say that there are no officers of this nature who are running away from their basic responsibilities. We have the programme for Parliamentarians also, and in spite of the programme that we have undertaken in the Parliamentary Association, we know the way some of us conduct ourselves. So, it is human nature. But I am in agreement that the programmes have to be implemented in their letter and spirit. But who is implementing the programmes? If Mr. Lakkappa is interested in the implementation of the programme, I may point out, the programme is implemented at the district level, at the block level and at the taluka level, not even at the State level. Barring one or two items under the 20-Point Programme where the administrative Ministries at the Centre are responsible, the rest of the programmes is implemented by the State Government, by the District Councils and even at the Panchayat Samiti level. I am happy to inform the House that, in some of the States, they have associated the non-official Members at the taluka level, at the block level and at the district level; maybe, in one or two States, they have associated the public representatives at the State level also. If any State Governments have been left out where the people's representatives have not been represented in the shape of MLAs or MLCs, Lok Sabha or Rajya Sabha Members and also Members of the District Councils, certainly we would like to request the State Government concerned that in the interest of the implementation of the programme, they should get these public representatives associated. I cannot possibly agree to the other suggestion that all the political parties be represented on these Implmentation Committees or Monitoring Committees. If they are all brought on these Committees, I can very well imagine what will happen. So, there is no point in having the representatives of all the political parties on the implementation side or even on monitoring. We have the monitoring stage in the Planning Commission. Administrative Ministries get monthly reports. Quarterly report is a kind of status report which the officers are supposed to compile. It is first compiled at the stage of the administrative Ministry. It is evaluatory in nature and it is sent to the Planning Commission. Thereafter, monitoring is also done in the Planning Commission. Thereafter, every six months, we have a meeting of the full Planning Commission wherein if possible we also request the Prime Minister to be present and she presides over the meeting where complete monitoring of all the 20-Point Programmes is done. The administrative Ministries have their own cells. At the State level, the Monitoring Committee is presided over by the Chief Minister. At the officers' level, it is presided over by the Chief Secretary. At the district level also there are Monitoring Committees. So, there are a large number of Monitoring Committees which have already been created; they are looking into the matter and are trying to solve the problem.

Another point which hon. Member Shri Ram Vilas Paswan raised is that it is very strange that in spite of monitoring there is the cost over-run and the time over-run and that projects costing Rs. 2 crores started some years ago have taken 10 years and 12 years for their completion and the project cost has escalated to such an extent that it has become almost uneconomic. How do you help the situation? I am in agreement with you. In the Sixth Plan at the time of the annual plan discussion we can guide the State Government. We can persuade them but if we expect that we can over-rule them, there, of course, the bigger question is bound to arise. I can also appreciate the difficulties of the State Governments. We have been telling them consistently that there are some projects which are being implemented for the last 10, 15 and 20 years and 'for God's sake, these projects which are in an advanced stage

[Shri S. B. Chavan]

should be completed and then you can start new projects.' We have been giving high priority to the projects which are at the advanced stage so that they can be completed in the Sixth Plan or to projects where the World Bank or some foreign agency is giving assistance. We give them priority and request the State Government that they should not start any new projects and the whatever limited resources are available, they should not unnecessarily spread very thinly. But the State Governments have also their own difficulties. I may not be surprised if I were to mention the names of some of the hon. Members of this House also who knowing full well that a large number of schemes have already been started and even for ongoing schemes we cannot provide the necessary funds, come to the administrative Ministries concerned and press for inclusion of one scheme or the other. In the House, they insist, 'No, you should not do this. You have to concentrate only on completion of the projects.' Sir, I hope I am not divulging any secret. But at the same time I must also bring to the notice of the House our difficulties and I will not be surprised if in a much bigger way, the same difficulties are also faced by some of the State Governments who are there to face the people. People go there, force them and pressurise them and willy-nilly they have to accept some small minor, medium and even major irrigation schemes. Then, having started it, everybody says that this scheme was started ten years ago. My friend, Mr. Daga—I do not know whether he is there—said the Rajasthan Canal was started in 1958 and 'even now we do not know how many years more it will take.' I have personally gone there. I have inquired into the scope of the project which was taken up in 1958. Can any hon. Member deny that the scope of the project has been enlarged? A large number of things which in fact were not contemplated in the 1958 project have been now included in the project. With the enlarged scope we would like a greater provision to be made. But having discussed with the Chief Minister we can give about Rs. 40 crores more with a specific understanding that this project is going to be completed in the Sixth Plan period. I have asked the Irrigation Ministry to prepare a very detailed programme of action and see that it is implemented according to the schedule that was decided upon as a kind of gentlemen's agreement. So, on that clear understanding we have given additional funds and I hope that specific portion of this Rajasthan Canal is going to be completed by the end of the Sixth Five Year Plan.

I will just make one other point and finish, because I do not think it is going to be possible for me to cover all the other points. A point was made about land reforms specially. I am sorry—Mr. Chitta Basu is not there. He raised it....

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr Sinha also mentioned it.

SHRI S. B. CHAVAN: But he had a definite point. Mr. Chitta Basu said that almost 50 per cent of the surplus land taken possession of has been contributed by one State. He has been after me for giving the figures. I have very detailed figurs with me which I can supply to him, that 50 per cent of the land taken possession for being distributed among poorer sections whether this is a correct statement is a matter which I would like to bring to his notice. I can give the figures. The number of returns filed voluntarily is 10,47,219 and on official initiative it is 3,88,373. The total number of returns filed comes to 14,35,663. The number of cases disposed of is 14,08,455 and the number of cases pending is just 27,208. But even these cases need to b expedited. There is no doubt aboutit. We have written to the State Governments that these pending cases need to be expedited and they should be disposed of. Now, I can give you the details of the total area. The hon. Member, Mr. Paswan, said all the area which was supposed to be surplus was 53 lakh but after all there is an estimate of the State governments. When they went in for Legislation their Estimate was that this much Land will be available. Now the area which has been declared surplus is 41,65,389 and the area taken possession of is 26,77,635 and the area distributed is about 19,57,996 and the number of beneficiaries is 14,32.944. I am giving the figures as on January, 1983.

So, there is a gap between land declared surplus and taken possession of and land taken possession of and distributed to the beneficiaries. There is a difference and that difference is because of the fact that area under court cases is 12,03,951 acres. Courts have given interlocutary orders, stay orders and writ petitions have been filed. I agree with the hon. Member when we have enacted so many legislations in Parliament why cann't we do something in order to see that courts do not intervene in the matter. The only course open to us is to bring the land reforms legislation under Schedule IX of the Constitution.

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: That is there.

SHRI S. B. CHAVAN: Some enactments have been covered under it and the rest of the enactments should be brought under Schedule IX. That position has been taken by the Government and legislation is being framed, if possible, I do not know whether the time is going to be available for introducing that Bill during the course of the Budget Session but the effort of the Government is to see that all the land reforms legislation gets covered under this so that at least under the Constitution the courts can be barred but inspite of it I can also bring it to the notice of the House that the courts have been taking notice of certain proceedings which have already been started.

Sir, Shri Vyas said what assistance has been given to all these allottees. Till 1981-82 Rs. 16.42 crores have been released to the different State Governments and they have been requested that these new allottees should be helped financially and also with the help of the community wherever this kind to social awareness is there, they have done a tremendous job and I must say that these allottees are quite happy in getting the land.

Sir, there is only one more point....

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: Mr. Deputy Speaker, Sir I would like the hon. Minister to explain one point. He has said that 26 lakh acres have been taken possession of by Government out of which....19 lakhs acres have been distributed. Now, the court cases will not interfere with this particular piece of land. 8 lakhs acres of land are already in possession with them. What is the snag is distributing that land? Why should there be delay?

SHRI S. B. CHAVAN: I was also under the same impression that since the Government has taken the possession, thereafter, the Courts will not interfere in the matter. But at least, I cannot be sure about it. The information given to me is this: Stay orders have been granted not only before taking possession but the Courts people even after possession have been taken by the State Government, have stopped them from distributing to the beneficiaries till the matter is settled at the Court. And of course, from place to place, things might differ; but the position remains the same. And we have requested the State Governments that they should immediately see that stay orders are vacated. And, even if necessary, they can request the Courts to constitute Special Benches in order to see that this programme is allowed to be implemented.

There is only one point and I have done.

This is about the misuse of the funds which are being given for poverty elevation. Cases are bound to be there in such a vast country such as ours; there are various programmes of this nature to be implemented by State Governments; crores of rupees are being distributed to the poorer sections; those people are not conscious of their rights; also the public representatives, somehow or the other, are not able to give them the kind of protection which in fact is expected of them. It is quite possible that some of the officers may misuse it. That is why now in the Rural Development Ministry, Special Task Force has been created. Regional offices have been set up. State Governments have been requested to physically verify the assets from which the incomes are supposed to accrue to the beneficiaries. So, this physical verification at the State Government level, by the regional offices of the Rural Development Ministry is there. A small Cell, a Task Force, in the Rural Development Ministry is there.

[Shri S. B. Chavan]

These are the three agencies which have been specially created so that they may go and physically verify, for instance, if certain cows which have to be given, have been given, or certain other things which the poorer sections are supposed to get, are given; it may be through the bank, or through direct subsidy which has been provided by the State Government; they have to see whether those things have passed on to the real hands, or whether the money has been mis-utilised. Now, if the money is mis-utilised, then certainly further action can be taken by the Government.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Chavan, how this happens is like this: Suppose a particular amount has to be spent before the end of the financial year, they do not want that amount to lapse. Therefore, they divert it to some other use. Suppose a rule is made that that amount will not lapse but it will be carried over for the same purpose,—If we can have a procedure or rule like that,—then this misuse will not be there. Suppose for Harijan uplift, Government allots Rs. 2 crores. Out of that, only Rs. 1.50 crore has been spent; now what they do is, they divert it to some other scheme. If this Rs. 50 lakhs can be carried over to next year for the same purpose, namely, Harijan uplift, —if you add Rs. 50 lakhs to make it Rs. 2.50 crores for the next year—then this trouble will not come.

SHRI S. B. CHAVAN Sir, non-lapsable funds are definitely provided. But this cannot be made applicable for all the schemes. Otherwise, the meaning of the Budget discussion in the House and the sanctity of the Budget will lose its significance. That is why we have to have some kind of a compromise whereby the schemes are allowed to be continued. But at the same time, because of rush at the end of the year, if they spend money in an improper maner, then, if the mistake is genuine, I don't think anybody is going to take serious note of it. Why they really linger on till the end is a matter which will have to be gone into. This is a matter which can be looked into.

I can assure hon. Members that Government is fully seized of the whole matter. Monitoring, right from the taluka level, the district level, the State level and thereafter, at the administartive ministry level, at the Planning Commission level, and even at the level of the Prime Minister, is being done.

So, Sir, there is no point in adding to it yet another machinery of monitoring, which, in fact, is not going to give us any results.

So, I make this request to Shri Lakkappa; I fully appreciate his sentiments. I fully appreciate the sincerity with which he has brought forward this resolution, but at the same time he would kindly understand the complications involved and he will not press for this kind of Resolution being passed by the House.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to the hon. Minister and also to the hon. Members sitting on this side and also on that side for appreciating my resolution. They have appreciated my Resolution and they have also wholeheartedly supported it. Sir, I cannot be so philosophical as our hon. Minister had been in his reply because for the problem of this nature he said that there was no need for any monitoring system, because it has already been created and it is enough. Sir, I would like to point out that the Parliament is Supreme and I think that the Parliament has to fulfil the wishes of the people of this country and the countrys immediate need is a rapid socio-economic change. I think that Parliament is one of the powerful forum where we can focus our attention and reflect the wishes of the people and with that end in view and with that spirit, this Resolution has been brought forward by me. It is not that I have not brought out all the facts in support of my Resolution. I have brought them out in an elaborate manner.

There are three important/vital issues in this Resolution. I have demanded the structural changes in the system of present administration which is a permanent body which would implement every policy of the Government. It is not that the policy of the Government and the Prime Minister's programmes are outside the 20-Point Programme. They are not different from those outlined in

the Five Year Plans. The policy is the national policy. As the entire House has agreed and the whole country has agreed, this is the system with which we are operating. But the operating machinery is blunt and that machinery is not operating properly. It is wrong machinery. We have had a number of Adminstrative Reforms, a number of Conventions, a number of Conferences and we have arrived at conclusions and made deliberations. What had happened to those deliberations and conclusions? Has any impact been brought about towards the structural changes in the administrative system. I have already mentioned about the bureaucratic delay, not only once, but several times, not only by me but several others in this House on several occasions that the system has to be changed, the machinery has to be changed. We have to bring about an egalitarian society in our country. That is the spirit behind the Constitution.

In a democratic country, Parliament is a powerful sovereign body. But the instrument which we use for the implementation of the various programmes for the weaker sections is blunt and if you don't sharpen that machinery, then what is the use of bringing out tall and flattering programmes and policies by the Government? If they are not implemented in the spirit in which they were formulated and the people do not get the results, it is illogical and against the principles of the democracy and the functionary becomes a farce.

Sir, the hon. Minister has placed before the House all the facts and appreciated by Resolution. But I would like to submit that all the schemes in the 20-Point Programmes are no other than those of the Prime Minister. It is not that I am not aware of that. There are various Cells in the Ministries and they have been operating to oversee the activities of the operating machinery. But if those activities are not supervised and checked as to whether they are functioning properly and effectively, then there is no use of having those Cells. They are functioning in that manner because there is no accountability and there is no responsibility. Have you ever pinpointed the responsibility for delays and failures in the implementation? Have you ever tried to find out whether the persons who were assigned the job of implementation did their job efficiently? if not, were they held responsible for that? You claim that you have got instruments and machinery for the implementation of the various schemes; you have a cell at the level of Planning Commission, at the Central level or at the State level, and even then we are failing in achieving our objectives. Has any responsibility been fixed at any time for these lapses?

The Government is accountable to Parliament. We have got certain parliamentary Committees, for example, Public Acounts. Committee, Committee on Public Undertakings and Estimates Committee. These are the Committee of Parliament, the sovereign body of this country. But these Committee have become a farce; we have no power to have their recommendations implemented. These Committee, in fact, do the post mortem, and the reports of these Committees as also other Committees are not taken up seriously either by the bureaucracy, or by the implementing agencies. These reports are placed on the Table of the House and sometimes discussions also take place in the House. But what do we achieve at the end? Are the recommendations taken seriously by the bureacracy?

These Committees are considered as the watchdog of the House, but that is no satisfaction to the people at large. They are concerned with quick results; they want revolutionary changes, they want immediate transformation of the society; they want to see for themselves effects of the various economic programmes of the Government. What do we find in effect? We all know that.

More than fifty per cent of our population is under-nourished. Though we have adopted a number of programmes for the upliftment of the poor people, but the performance has been far from satisfactory. We have started a number of programmes like the Integrated Rural

[Shri K. Lakkappa]

Development, National Malaria Eradication Programme, the National Rural Employment Programme, and allotted a lot of money for them but what has been the performances? Have the results percolated down to the poor people? There is a programme for removal of rural indebtedness also, but it has not really helped the people as it should.

In this connection, I would like to quote what appeared in the *Indian Express* on 8th July, 1982 which indicated that the progress of 20-Point Plan was disappointed :

> "The States whose performance is adjudged poor are Karnataka, Assam, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Manipur, Haryana, Gujarat, Sikkim, Maharashtra and Rajasthan. Uttar Pradesh failed to report its performance on integrated rural development."

About the national rural employment programme, it was stated:

> "...the performances of Assam, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab and Sikkim are adjudged poor, of Karnataka, Kerala and Maharashtra as negligible."

I would also like to quote, in this context, what was stated in the statement referred to in reply to part (a) of Lok Sabha Unstarred Question No. 2203, for answer on July 21, 1982 about the pointwise physical achievement upto May, 1982:

> IRDP—target 20.96 lakh nos., achieved 10.99 lakh nos.
>
> NREP—target 3311.20 lakh nos, achieved 97.72 lakh nos.
>
> Land Reforms, target 1133.10 thousand acres, achieved 5.11 thousand acres.

This statement also indicates the targets and the achievements in respect of bounded/labour, SC and ST families, problem villages, house sites, slum population, villages electrified, trees planted, bio-gas, sterilisation etc. Nowhere, it is near the target.

I am quoting these figures to substantiate my claim that we are far behind our goal. Most of the States do not spend the money allotted to them under the various socio-economic programmes.

There is, therefore, today a vital need for the speedy implementation of the various socio-economic programmes. A resolution from this House will go a long way in shaking up the implementing machinery from their slumber. There should be a monitoring body under the Government to oversee the activities at various levels. It will create a lot of confidence in the minds of the people.

It will become a powerful instrument to oversee the activities and fix accountability and responsibility for administrative delays or any lapse or misappropriation or faulty planning for improper administrative arrangement. This is very necessary in the larger interest of the nation and quicker progress of the social and economic programme. Therefore, I want, not on artificial grounds, but on points and reasons in keeping with the aspirations of the people that the Hon. Minister should assure us that he will see that some such monitoring system is set up to oversee all this work from top level down to the village level and see that the socio-economic transformation is brought about at a quicker pace. I know the Hon. Minister, Shri Chavan. He is a great friend of mine. I know he believes in the socio-economic reforms. Therefore, I request him to see that some such system is evolved for bringing about quicker transformation in our socio-economic set up.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you pressing or withdrawing the Resolution?

SHRI K. LAKKAPPA : I am urging the Minister. Let us see what he says.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I have already stated that I appreciate the points the Hon. Member has put forward. I also appreciate the spirit in which these points have been put forward. I assure him that we are interested in doing that.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek the leave of the House of withdraw Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

18.52 hrs.

RESOLUTION RE: RIGHT TO WORK AS FUNDAMENTAL RIGHT

SHRI CHANDU LAL CHANDRAKAR (Durg): I beg to move :

"बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह "काम के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिये कार्यवाही करें।"

RESIGNATION OF MEMBER

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to inform the House that the Speaker has received a letter dated 28th February, 1983 from Dr. Farooq Abdulla, an elected Member from Srinagar Constituency of Jammu and Kashmir resigning his seat in Lok Sabha with effect from 1st March, 1983 (forenoon). The Speaker has accepted his resignation with effect from today, the 4th March, 1983.

The House stands adjourned till 11 a.m. on Monday, the 14th March, 1983.

18.53 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, 14, 1983/ Phalguna 23, 1904 (Saka).

GMGIPND—M—3379 LS—18-7-83—890